3 किसान परेशान, नहीं हो रहा मूंग का भुगतान

5 राजवीरों की बात में इस बार निर्मला सीतारमण

7 आरएसएस प्रतिबंध से विचार नहीं मिटते

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 16 प्रति सोमवार, 26 अगस्त 2024 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

पौधारोपण में इंदौर ने रचा नया कीर्तिमान, एक दिन रोपे गए 11 लाख पौधे

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

एडिटर

इंदौर शहर कई क्षेत्रों में पहल कर एक नई पहचान बना चुका है। अब पौधारोपण के क्षेत्र में भी वह अपनी एक विशेष पहचान स्थापित करने में सफल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण को जनांदोलन बनाते हुए देश की जनता से एक पौधा अपनी मां

पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन में भी नंबर वन इंदौर

कैलाश विजयवर्गीय को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मिलना चाहिए उत्कृष्ट पुरूस्कार

के नाम से रोपने का आह्वान किया है। इस आंदोलन को अमली जामा पहनाते हुए 14 जुलाई को इंदौर में 12 घंटे से भी कम समय में 11 लाख पौधे रोपे गए, जिसे गिनीज रिकॉर्ड द्वारा एक विश्व कीर्तिमान घोषित किया गया है। (शेष पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग के साथ मिलकर किया छत्तीसगढ़ के विकास पर मंथन

विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से कार्य योजना तैयार कर रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रीमंडल और उसके सदस्य मिलकर लगातार जनकल्याण की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच साय सरकार द्वारा किये जा रहे नवाचारों की चर्चा अब न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी हो रही है। पिछले दिनों अपनी तरह की अनूठी पहल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत की संकल्पना के अपने विजन के क्रियान्वयन के लिए आईआईएम एवं देश भर की प्रतिष्ठित संस्थाओं के विषय विशेषज्ञों के साथ मंथन किया। रायपुर आईआईएम में आयोजित इस दो दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया। शिविर में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा तथा मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों ने भी हिस्सा लिया। इस तरह से देश में विषय विशेषज्ञों के साथ बौद्धिक विमर्श और चिंतन शिविर गुजरात में आयोजित किया गया था।

विशेषज्ञों से संवाद में निकला विकास का आयाम

देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का पूरा मंत्रिमंडल प्रदेश को संवारने एवं विकास को नया आयाम देने विद्यार्थी भाव से विचार-विमर्श करने जुटा है और अपने क्षेत्र के माने हुए विषय विशेषज्ञों से संवाद कर रहा है। प्रदेश के नेतृत्व द्वारा इस तरह से अनूठी पहल करते हुए विशेषज्ञों से बौद्धिक विचार-विमर्श कर प्रदेश को संवारने के लिए आज सार्थक चर्चा की गई। (शेष पेज 2 पर)

राज्य के छात्रों को शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने की छत्तीसगढ़ में हुई पहल

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। लाइब्रेरी को "नॉलेज बेस्ड सोसायटी" यानी "ज्ञान आधारित समाज'' के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में स्थापित किया जाएगा। इस लाइब्रेरी से उन छात्राओं को मदद मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके साथ ही अलग-अलग एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को भी मदद मिलेगी।

शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने का संकल्प

वित्त मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने संकल्पित है। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी की सौगात दी है, जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। (शेष पेज 3 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग के साथ मिलकर किया छत्तीसगढ़ के विकास पर मंथन

(पेज 1 का शेष)

छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बनाये गये विजन के क्रियान्वयन के लिए आज दिन भर हुए सत्रों में गहन विचार विमर्श किया गया। जैसे कोई कृषक बड़ी मेहनत से खेती के लिए अपनी जमीन तैयार करता है वैसा ही विकसित छत्तीसगढ़ के स्वप्न को मूर्त रूप देने छत्तीसगढ़ का शीर्ष नेतृत्व जुटा, जो विजन तैयार किया गया है उसे प्रभावी बनाने विषय विशेषज्ञों से राय ली गई ताकि उनके सुझाव लेकर विजन के क्रियान्वयन को पैनापन दिया जा सके।

विकास की संभावनाओं पर हुई चर्चा

चिंतन शिविर में तय किया गया कि विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को समाज के सभी वर्गों के बीच ले जाना है। सबको जागरूक कर और उनकी भागीदारी लेकर विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों को पूरा किया जाना है। शिविर में विषय विशेषज्ञों के साथ देर तक चर्चा हुई और छत्तीसगढ़ की संभावनाओं को लेकर बारीकियों पर बात हुई।

विकसित भारत 2047 बनाने का संकल्प

नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने विकसित भारत की संकल्पना और इसे प्राप्त करने की रणनीति के संबंध में विस्तार से अपनी बातें साझा की। उन्होंने कहा कि बीते दस सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2047 बनाने का संकल्प लिया है और इसे पूरा करने की रणनीति बनाई है। सुब्रमण्यम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्केल, स्पीड और इनोवेशन पर जोर देते हैं। बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और समय को देखते हुए विकसित भारत का विजन तैयार किया गया है ताकि भारत अपनी विशिष्ट जगह बना सकें। उन्होंने कहा कि अब दुनिया की निगाहें ग्लोबल साउथ पर हैं।

महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

अब दुनिया का नजरिया पश्चिम से पूर्व की ओर देखने का है और भारत इन संभावनाओं को पूरा करने के लिए सक्षम है। भारत की जनांकिकी, भारत की रणनीतिक स्थिति और भारत में तेजी से हुए सुधारों से इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत तैयार है। उन्होंने कहा कि जब हम विजन लेकर चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें एक गाइड मैप मिल जाता है और इसके अनुरूप हम बढ़ते जाते हैं। सुब्रमण्यम ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में छत्तीसगढ़ की अहम भागीदारी होगी। छत्तीसगढ़ में विकसित राज्य बनने के लिए और तीव्र विकास के लिए असीम संभावनाएं हैं और इस दिशा में आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ अपने विकास के साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है

चिंतन शिविर में स्वास्थ्य, अधोसंरचना, खनन, लोकवित्त जैसे बुनियादी विषयों पर चर्चा हुई जिनमें बारीकी से कामकर और सही रणनीति बनाकर विकसित छत्तीसगढ़ और लोगों की समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। स्वास्थ्य में अधोसंरचना पर जोर दिया गया। कोविड जैसी आपदाओं से भविष्य में निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से चाकचौबंद रखने पर जोर दिया गया। साथ ही इस क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने और निरंतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने चर्चा की गई।

प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग

प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग विषय पर भी चर्चा हुई। खनन में अनेक राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाने के संबंध में बात हुई। साथ ही खनन के पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कार्य करने की जरूरत पर जोर दिया गया। आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किए जाने पर विशेष फोकस दिया गया। शहरों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भीतरी सड़कों के विकास पर बल दिया गया ताकि विकसित अधोसंरचना के माध्यम से आर्थिक समृद्धि सभी क्षेत्रों तक बराबरी से पहुंच पाए। लोक वित्त पर भी गहनता से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ की ताकत सरप्लस रेवेन्यू, फिस्कल डिसिप्लिन, लो डेब्ट एंड जीडीपी रेश्यो, खनिज एवं वनसंपदा पर जोर देते हुए कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, फसल वैविध्य, उद्योगों और टूरिज्म के अनुरूप मानव संसाधन को दक्ष बनाने की जरूरत पर बल दिया गया।

पौधारोपण में इंदौर ने रचा नया कीर्तिमान, एक दिन रोपे गए 11 लाख पौधे

(पेज 1 का शेष)

इंदौर के शीर्ष भाजपा नेता एवं मध्य प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा शहर में 51 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में पौधारोपण किया। उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत रेवती रेंज में पीपल का पेड़ लगाया है। इस दौरान एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। इससे पहले अमित शाह ने पितृ पर्वत पर पित्रेश्वर हनुमान मंदिर में दर्शन किए।

धर्म हरेक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विषय होता है, उसी प्रकार भक्ति भी। ऐसी ही भक्ति भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय की "पित्रेश्वर हनुमान धाम" को लेकर नजर आती है। पित्रेश्वर हनुमान धाम, पितृ पर्वत इंदौर में स्वयं कैलाश विजयवर्गीय ने निर्माण करवाया है। इंदौर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित पितरेश्वर हनुमान भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। यहां हनुमान जी अपने वृहद आकार में ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं। साथ ही भगवान श्रीराम की भक्ति कर रहे हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी अष्ट धातु की प्रतिमा है। पितरेश्वर हनुमान मूर्ति को लगवाने से लेकर प्राण-प्रतिष्ठा तक का श्रेय बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को जाता है। कैलाश विजयवर्गीय जब 2002 में इंदौर के महापौर थे। इस दौरान उन्होंने गोमटगिरी पहाड़ी के सामने देवधरम टेकरी पर बैठे हनुमानजी की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाने का फैसला किया था। उन्होंने शहर के लोगों से आग्रह किया कि वे 'पितृ पर्वत' पर अपने पितरों के नाम से एक पौधा लगाएं। इसकी शुरुआत हुई तो 20 सालों में लोगों ने पितृ पर्वत पर हजारों पौधे रोपे। इस पर्वत में हनुमान जी के मंदिर और विशाल मूर्ति के अलावा गौशाला भी है। साथ ही लोगों ने करीब-करीब तीन लाख पौधे अपने पितरों का स्मरण करते हुए लगवाया है। पर इससे इतर कैलाश विजयवर्गीय ने इस धाम को लेकर कभी श्रेय नहीं लिया है, उनकी भक्ति भी श्रेष्ठ है। कैलाश विजयवर्गीय को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरूस्कार मिलना चाहिए। मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नेक पहल करते हुए पितृ पर्वत में स्थान ग्रहण किया है। खास बात यह है कि यह वही पितृ पर्वत हैं जिसकी स्थापना कई वर्षों पूर्व कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की जनता के विकास के संकल्प के साथ की थी। निरंतर कई वर्षों से कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन की दिशा में उठाया गया उनका यह कदम निश्चय ही प्रशंसनीय है। मुझे याद आता है कि लगभग 24 वर्ष पहले जब कैलाश विजयवर्गीय ने पितृ पर्वत पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी उसी समय उन्होंने अन्न त्यागने का फैसला किया था। वे लगभग 20 वर्षों तक अपने इस फैसले पर अडिग रहे और उन्होंने लगभग दो दशकों तक मुंह में अन्न का दाना तक नहीं रखा। अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहते हुए विजयवर्गीय ने वर्ष 2020 में विशेष अनुष्ठान-अर्चना कर अन्न ग्रहण किया। कैलाश विजयवर्गीय सन 2000 में जब इंदौर के महापौर बनें हुए उस समय उन्हें किसी संत ने बताया था कि शहर पितृ दोष से ग्रस्त है और इसी वजह से इंदौर का विकास अवरुद्ध है। इसके उपाय के तौर पर यह बताया गया कि अगर इंदौर के पितृ पर्वत पर भगवान श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाए तो यह दोष दूर हो सकता है। भाजपा कैलाश विजयवर्गीय ने अपने जन्मस्थान इंदौर की उन्नति के लिए संकल्प लिया कि वह जब तक पितृ पर्वत पर विश्व की सबसे ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित नहीं कराएंगे तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अब 20 साल बाद जाकर उनका यह संकल्प पूरा हुआ है। इंदौर के पितृ पर्वत पर 72 फीट ऊंची, 108 टन वजन की अष्टधातु की हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस पर करीब 15 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, संत मुरारी बापू और वृंदावन से महामंडलेश्वर गुरुशरणानंदजी महाराज की उपस्थित में कैलाश विजवर्गीय ने 20 साल बाद संकल्प पूरा होने पर अन्न ग्रहण किया। लेकिन इन 20 वर्षों में उनके इस संकल्प के दौरान उनकी पत्नी आशा विजयवर्गीय ने पूरा सहयोग दिया और उन्हें फल, साबूदाने, सवा के चावल वगैरह की खाद्य सामग्री खाने के लिए दी। इतना ही नहीं इन 20 वर्षों में कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों का आह्वान किया कि वे अपने पूर्वजों की याद में पितृ पर्वत पर पेड़ लगाएं। इस तरह दो दशकों में लगभग यहां एक लाख पौधे लगाए गए जो वृक्ष बन चुके हैं। अपने शहर को एक दोषमुक्त शहर से उबारकर विकसित शहर बनाने की दिशा में अनेकों पहल करने वाले कैलाश विजयवर्गीय का कार्य सचमुच प्रशंसनीय और पुरस्कृत करने योग्य है।

कैसे कैलाश विजयवर्गीय ने पितृ पर्वत की परिकल्पना साकार की

'पितृ पर्वत' की मूल परिकल्पना सिर्फ एक बंजर पहाड़ी को हराभरा बनाकर पितरों की स्मृति को स्थायी बनाए रखने की थी लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया इस संकल्प ने नई-नई योजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना आरंभ कर दिया। यहीं एक कार्यक्रम में जब पर्वत पर हनुमानजी की प्रतिमा लगाने का सुझाव आया तो दूसरे ही पल इस कल्पना को साकार करने वाले मुख्य सूत्रधार श्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से ही मूर्तिकार से मूर्ति निर्माण के लिए चर्चा कर ली। यह पूछे जाने पर कि मूर्ति कितनी बड़ी होगी, श्री विजयवर्गीय ने कहा -जितनी विशाल आप बना सकें। इसी के साथ अष्ट धातु की 71 फ़ीट ऊंची 54 फ़ीट चौड़ी और 108 टन वजन की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण शुरू हो गया था। इस प्रतिमा की खासियत यह है कि यह सात चक्रों वाली है जो भक्तों के कल्याण के साथ इंदौर शहर के वास्तु को भी ठीक करेगी। भजन करते हुए बैठे हनुमानजी की यह देश की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इनके साथ यहां प्राचीन शिव मन्दिर, बाल हनुमान मंदिर, भैरूबाबा मंदिर, पितरेश्वर हनुमान मंदिर और माता अंजना मंदिर भी शामिल हैं जिनके स्थापित होने से यह स्थल 'पितरेश्वर हनुमान धाम' के नाम से जाना जा रहा है।

बंजर था पितृ पर्वत, लगवाए 01 लाख पेड़

नगर निगम इंदौर ने इस पहाड़ पर पंप हाउस बना कर रखा था। पूरा पहाड़ बंजर था। कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों का आह्वान किया कि वे अपने पूर्वजों की याद में पितृ पर्वत पर पेड़ लगाएं। इस तरह दो दशकों में लगभग यहां एक लाख पौधे लगाए गए जो वृक्ष बन चुके हैं। उनके इस संकल्प के दौरान उनकी पत्नी आशा विजयवर्गीय ने पूरा सहयोग दिया और उन्हें फल, साबूदाने, सवा के चावल वगैरह की खाद्य सामग्री खाने के लिए दी।

इसके पूर्व 2002 से ही इंदौर में पौधारोपण को लेकर विशेष पहल शुरू हो चुकी थी। तत्कालीन महापौर के रूप में कैलाश विजयवर्गीय ने एक वृहद् पौधारोपण योजना बनाई थी। इसके अंतर्गत इंदौर हवाईअड्डे से मात्र तीन किमी की दूरी पर स्थित धरम टेकरी नामक स्थान को चिन्हित किया गया था। यहां वृहद् स्तर पर पौधारोपण किया गया और जनता को भी प्रेरित किया गया कि यहां पर अपने पूर्वजों की स्मृति में पौधारोपण करें। इसी से जोड़ते हुए इस स्थान का नाम परिवर्तित कर 'पितृ पर्वत' कर दिया गया। आम लोगों के साथ ही विशिष्टजन भी यहां अपने पूर्वजों के नाम से पौधारोपण करते हैं। अब तक यहां लाखों पेड़ लगाए जा चुके हैं।

विराजमान है अष्टधातु की 108 टन वजन की हनुमान जी की इस विशाल मूर्ति

इसके साथ ही यहां हनुमान जी की देश की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। इसके लिए 125 विशेष कारीगरों ने अष्टधातु की 108 टन वजन की हनुमान जी की इस विशाल मूर्ति का निर्माण किया। बैठे हुए हनुमान जी की इस 72 फीट ऊंची मूर्ति को बनने में सात वर्ष लगे। अत्यंत आकर्षक सुनहरे रंग की यह मूर्ति आज शहर की प्रमुख पहचान बन चुकी है। पितृ पर्वत पर स्थित इस भव्य मूर्ति को पितरेश्वर हनुमान जी के नाम से जाना जाता है।

सामाजिक संस्थाओं का भी मिल रहा सहयोग

51 लाख पौधे रोपने के इस अभियान में शहर का हर समाज, वर्ग, संस्था, संगठन आगे आ गए। देश के अन्य हिस्सों ने भी मदद का हाथ आगे कर दिया। 20 करोड़ रुपए के पौधे तो इस संकल्प को दान में ही मिल गए। 300 से ज्यादा ट्रकों में ये पौधे आंध्रप्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों से शहर में आए। आज इंदौर इसके कारण ही विश्व कीर्तिमान रचने जा रहा है। एक ही दिन में 11 लाख पौधों का रोपण कर ये रिकॉर्ड बनेगा। इसके लिए 50 हजार से ज्यादा इंदौरी जुटेंगे। इसकी शुरुआत रविवार सुबह से हो गई। रेवती रेंज का नजारा किसी मेले से कम नजर नहीं आ रहा है। यहां अलग-अलग समाजों को अलग-अलग स्थान दिए गए और बड़ी संख्या में समाजजन का यहां सुबह 8 बजे से ही आना शुरू हो गया। स्वयं विजयवर्गीय व महापौर पुष्यमित्र भार्गव इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

क्या कहा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने

पहले इंदौर में तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस रहता था। मालवा में तापमान कभी 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होता था, लेकिन इस बार यह 48 डिग्री तक पहुंच गया है, यह बड़ी समस्या है। मैंने तभी संकल्प लिया था और कहा था कि पांच साल में तापमान पांच डिग्री कम करना है। हमने 51 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। इंदौर में हर साल 51 लाख पेड़ लगाने के बाद इंदौर का तापमान पांच डिग्री कम हो जाएगा। यह संकल्प संतों और आम लोगों के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता।

किसान परेशान, नहीं हो रहा मूंग का भुगतान

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। समर्थन मूल्य पर बेंची गई मूंग का भुगतान नही होने से किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर गुरुवार को किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि किसानों द्वारा 1 माह पूर्व समर्थन मूल्य पर शासन द्वारा अधिकृत वेयर हाउसों में जो मूंग बेची गई थी उसका भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ है जिससे किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। उक्त भुगतान को 7 दिवस में कराया जाये अन्यथा किसान भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर जाकर धरना देने के लिए विवश होंगे। ज्ञापन देने आए किसानों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मूंग का जो अभी तक शासन द्वारा भुगतान किया गया है उस में भी सहकारी बैंकों के खाते में कोई राशि नहीं पहुंची है। इस त्रुटि को भी दूर किया जाए। किसानों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार किसानों के हित की बात करती है और भुगतान के लिए लटकाया जा रहा है। भुगतान न होने के कारण किसान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। उक्त मौके पर प्रतीक शर्मा, आनन्द कौरव, नरेश रजक, सचित शर्मा, तिलकराज कौरव, छूटू कौरव, अमन शर्मा, विष्णु कौरव, कुलदीप कौरव सहित अनेक किसान मौजूद थे।

राज्य में 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, जल्द होगा निर्माण कार्य

(पेज 1 का शेष)

वित्त विभाग ने रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है।

500 और 200 सीटर लाइब्रेरी का होगा निर्माण

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इन लाइब्रेरियों का निर्माण सभी 13 नगरीय निकाय क्षेत्रों में किया जाएगा जिसके छात्रों को अपनी तैयारी करने में मदद मिले।

वित्त मंत्री ने बजट में की थी घोषणा

यह उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा, जो छोटे शहरों में रहकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी निर्माण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने मुख्य बजट भाषण में भी इसका जिक्र करते हुए कहा था कि युवाओं के अध्ययन के लिए नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी निर्माण किया जाएगा।

युवाओं के लिए प्रेरणा

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन केंद्रों को ''नॉलेज बेस्ड सोसायटी'' यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत और सरकार के लिए एक आदर्श बन सके।

मंदिर में चोरी करने वाला गिरफ्तार

-कैलाश चंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। 17 अगस्त 2024 को दिन में कोई अज्ञात व्यक्ति सोराई राम जानकी मंदिर से राम दरबार की मूर्तियों पर लगे तीन चांदी के मुकुट चोरी कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर से कोतवाली विदिशा में अपराध क्रमांक 561/2024 धारा 305(d) BNS का पंजीबद्ध किया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे एवं नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह के मार्गदर्शन में एक टीम को गठित किया गया। उक्त टीम की तत्परता से सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर द्वारा सूचना पर उक्त चोरी करने वाले हुलिया वाले एक व्यक्ति को पकड़ा जिसने अपना नाम शुभम गोस्वामी बताया जिससे पूछताछ करने पर सोराई मंदिर से मुकुट चोरी करना स्वीकार किया, आरोपी शुभम गोस्वामी को गिरफ्तार कर चोरी किए गए मशरूका के बारे में पूछताछ करने पर शिवाजी चौक के पास अनिल कुमार सोनी की सोने चांदी की दुकान पर बेचना बताया, पुलिस द्वारा अनिल कुमार सोनी निवासी सिंधी कॉलोनी से चोरी गए मुकुट बरामद किए गए एवं आरोपी अनिल सोनी को धारा 317(2) के तहत प्रकरण में आरोपी बनाया गया एवं धारा 35(3) का नोटिस दिया गया, आरोपी शुभम गोस्वामी को माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। शासकीय स्नातक महाविद्यालय टिमरनी में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की सफलता का 1 वर्ष पूर्ण होने पर दो दिवस का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम मनाया गया। जिसके प्रथम दिन में छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस से संबंधित जानकारी प्रदान की गई, साथ ही छात्र-छात्राओं को चंद्रयान-3 मिशन के बारे में महाविद्यालय की भौतिक शास्त्र प्रभारी सुरभि चौरे द्वारा संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। कई छात्र-छात्राओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के चंद्रयान-3 मिशन से संबंधित चित्र बनाए गए। कार्यक्रम के द्वितीय दिवस में महाविद्यालय के प्राध्यापकों में डॉ. सुनील कुमार बौरासी, डॉ. सादिया पटेल, सुश्री मीनाक्षी यादव, डॉ संजय पटवा, सुनित काशिव द्वारा छात्रों को मोटिवेट करने के लिए कई रोचक तथ्यों एवं वैज्ञानिकों के जीवन परिचय का वर्णन किया गया, साथ ही भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की जीवनी एवं उनके द्वारा किए गए महान कार्यों से संबंधित इसरो के पोर्टल द्वारा मूवी दिखाई गई एवं चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग संबंधित मूवी दिखाई गई। संपूर्ण कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं का विशेष रुझान दिखा एवं उन्होंने कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

छत्तीसगढ़ के महान वीर क्रांतिकारियों के जीवनवृत्त पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का समापन

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर।जनसम्पर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के महान वीर क्रांतिकारियों के जीवनवृत्त पर आधारित इस छायाचित्र प्रदर्शनी को विद्यार्थियों, युवाओं सहित सभी वर्ग के लोगों ने सराहा। 15 अगस्त से 21 अगस्त लगाई गई इस प्रदर्शनी का समापन हुआ। प्रदर्शनी स्थल पर युवाओं के लिए क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित टाउन हॉल में इस प्रदर्शनी को देखने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी, युवाओं और विभिन्न वर्ग के लोग आए। इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारियों की स्मृतियों को बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया था। यह प्रदर्शनी स्कूली विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए ज्ञानवर्धक रही। प्रतिदिन यहां प्रदर्शनी देखने के लिए आने वाले स्कूली विद्यार्थियों के मध्य क्विज प्रतियोगिता एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें विजयी प्रतिभागियों को तत्काल मिलने वाले पुरस्कार से प्रदर्शनी को लेकर स्कूली विद्यार्थियों और युवाओं में उत्सुकता रही। क्विज प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, पुरातत्व पर्यटन, संस्कृति, लोक कला, खेती-किसानी सहित अन्य विषय पर आधारित प्रश्न पूछे गए और सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। उल्लेखनीय है कि इस प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विगत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया था। सात दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी में आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों का योगदान और उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज, स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान उनकी जीवन यात्रा, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आन्दोलन एवं स्वतन्त्रता आंदोलन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में उनके योगदानों को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही मुख्य योजनाओं जैसे महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, रामलला दर्शन योजना, कृषक उन्नति योजना, महिला सशक्तीकरण, पीएम जनमन योजना, मुख्यमंत्री जनदर्शन आदि योजनाओं को प्रमुख रूप से शामिल किया गया। प्रदर्शनी स्थल पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर आधारित डाक्यूमेंट्री फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में आगंतुको को छत्तीसगढ़ राज्य शासन के लोक कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित विभिन्न पुस्तकों का भी वितरण निःशुल्क किया गया।

जनसम्पर्क विभाग की सात दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी को सराहा

सम्पादकीय

राम मंदिर और आर्टिकल 370 के बाद यूसीसी पर सरकार का फोकस

देश का वर्तमान सिविल कोड कम्युनल है। आजादी के 75 साल बाद अब देश में सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए।' जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बात को कहा था तो मेसेज साफ था जल्द ही यूनिफार्म सिविल कोड पर फैसला होने वाला है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि, प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बल्कि सेकुलर सिविल कोड शब्द का उपयोग किया। 'यूनिफॉर्म' के स्थान पर सेकुलर शब्द का उपयोग करना एक तय रणनीति का हिस्सा है। आखिर राम मंदिर और आर्टिकल 370 के बाद अब UCC पर ही सरकार का फोकस है। राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड- भारतीय जनता पार्टी द्वारा तय किये गए तीन एजेंडे थे। दो मुद्दों पर भाजपा अपना वादा निभा चुकी है अब बारी तीसरे वादे की है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा तीन टारगेट सेट किए गए थे। इनमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा एजेंडा था जिसकी चर्चा से सबसे ज्यादा असहज अल्पसंख्यक समुदाय होता रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से जब सेकुलर सिविल कोड का जिक्र कर रहे थे तब मंच पर बैठे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ मुस्कुरा रहे थे। पीएम मोदी द्वारा भाषण में 'सेकुलर सिविल कोड' का उपयोग यूंही नहीं किया गया। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे पहले समझते हैं UCC कैसे बना राजनीतिक मुद्दा। एक महिला के साथ हुए अन्याय से कैसे देश के राजनीतिक माहौल में उथल - पुथल आ सकती है यह जानने के लिए शाह बानो केस सबसे अच्छा उदाहरण है। इस केस के बाद ही संविधान का आर्टिकल 44 संविधान से निकलकर भाजपा के मेनिफेस्टो में पहुंच गया। दरअसल, बात 179 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता की थी। शाह बानो को उनके पति ने तलाक दे दिया था। गुजारा भत्ता के लिए उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। जब मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब जाकर शाह बानो को न्याय मिला। शाह बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में 5 न्यायाधीशों की पीठ फैसला करने बैठी। इनमें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन, न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अप्रैल 1985 में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए भरण-पोषण को बरकरार रखा और शाह बानो के पति को लागत के रूप में 10,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि, पांच बच्चों के साथ रहने वाली तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाह बानो के पूर्व पति को इद्दत (शरिया कानूनों के तहत मुस्लिम महिलाओं को दी जाने वाली राशि) के अलावा 179 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता के रूप में देना होगा। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। शाह बनो अदालत में तो लड़ाई जीत गईं लेकिन अदालत के बाहर की लड़ाई बाकी थी।

सियासी गहमागहमी

बघेल की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी

पिछले पांच सालों में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भूपेश बघेल ने जो भी भ्रष्टाचार के कार्यों को अंजाम दिया है अब उनकी परते खुलना शुरू हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार महादेव सट्टा एप मामले में प्रमुख आरोपी रहे बघेल को सीबीआई की एक टीम कभी भी गिरफ्तार करने रायपुर पहुंच सकती है। बघेल को अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा है शायद यही वजह है कि वे लगातार कांग्रेस आलाकमान के आगे पीछे होकर खुद को राज्यसभा कोटे से संसद भवन तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार बघेल के अलावा उनके करीबी लोगों पर भी एक बार फिर सीबीआई की एक टीम शिंकजा कस सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि बघेल सीबीआई के इस जाल से खुद को किस तरह से बचा पाते हैं।

शक्ति प्रदर्शन का दौर है जारी

मध्यप्रदेश भाजपा की राजधानी भोपाल की दो विधानसभा सीटों पर इन दिनों जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। पहले तिरंगा यात्रा और अब रक्षाबंधन महोत्सव को लेकर नरेला और हुजूर विधानसभा मे जबरदस्त कॉम्पिटीशन का दौर जारी है। दोनों ही नेता विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से लगातार इस तरह के सामाजिक आयोजन करने में जुटे हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि दोनों ही राजनेता आगामी मंत्रीमंडल विस्तार में अपनी सीट पक्की करने जुटे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार आगामी मंत्रीमंडल में वर्तमान मंत्री विश्वास सारंग का पत्ता काटे जाने की चर्चा है ऐसे में भोपाल सीट से रामेश्वर शर्मा अपनी दावेदारी को तेज करने के लिये इस तरह के आयोजनों की बौछार लगाये हुए हैं।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार है।

संविधान हर एक भारतीय को न्याय और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि देश की जनसंख्या के 90% के लिए न तो अवसर है और न ही तरक्की में उनकी भागीदारी है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

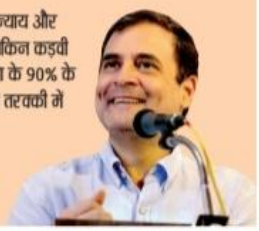

कृषकों के आराध्य देव, भगवान श्री कृष्ण जी के ज्येष्ठ भ्राता, भगवान बलराम जी की जयंती व हलछठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

हमारे सभी किसान भाई खुशहाल रहे , सुख, समृद्धि , प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, यही कामना है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

निर्मला सीतारमणः एक साधारण महिला की छलांग जिसने वित्त मंत्रालय में बनाई अपनी जगह

समता पाठक/जगत प्रवाह

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में उन्होंने अपना 65वां जन्मदिवस मनाया। देश भर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा "केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। निर्मला जी विकास और सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रही हैं। निर्मला सीतारमण का जन्म तमिलनाडु के एक साधारण परिवार में 18 अगस्त 1959 को हुआ था। उनके पिता रेलवे में नौकरी करते थे। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई अलग-अलग शहरों में हुई। इसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक किया और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। यहीं उनका रूझान राजनीति की ओर हुआ। इंडो-यूरोपियन टेक्सटाइल ट्रेड में अपनी पीएचडी पूर्ण की। इसी दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर पराकाला प्रभाकर से हुई, जिन्हें बाद में उन्होंने अपना जीवनसाथी बना लिया। पढ़ाई के दौरान नौकरी भी की और फिर पति के साथ लंदन चली गई। लंदन में उन्हें एक होम हेकोर की दुकान में सेल्स गर्ल का काम करना पड़ा। फिर वो वापस भारत आई और हैदराबाद में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी में डेप्युटी डायरेक्टर की नौकरी की। निर्मला सीतारमण के सास-ससुर कांग्रेसी नेता थे। उसके बावजूद साल 2008 में निर्मला सीतारमण ने बीजेपी ज्वाइन की, तब उन्हें पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया। साल 2014 में जब केंद्र में बीजेपी का सरकार बनी तो उन्हें मोदी सरकार में अहम जिम्मेदारी दी गई और साल 2016 में वो कर्नाटक सीट से राज्यसभा सदस्य बनी। उसी साल कैबिनेट विस्तार में उन्हें वाणिज्य और उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) में राज्यमंत्री बनाया गया। 03 सितंबर 2017 को निर्मला सीतारमण पहली बार देश की पहली पूर्ण रक्षामंत्री बनी। इसके अलावा वो सुखोई- 30 एमकेआई में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला रक्षामंत्री के रूप में उनके नाम अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। साल 2017 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली दूसरी महिला बनी।

मित्रता, प्रेम, भक्ति, करुणा, दया, धर्म के मिश्रित रुप है श्रीकृष्ण

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

जगत प्रवाह. भोपाल। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भारत में धूम धाम से मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो हिंदू माह श्रावण के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन मनाया जाता है। यह दिन भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। लोग इसे खुशी से मनाते हैं। श्रीकृष्ण मित्रता, प्रेम, भक्ति, करुणा, दया, धर्म के मिश्रित रुप है। भगवान श्रीकृष्ण ने अपने जीवन में इन सभी रूपों में अहम भूमिका निभाई है। जन्माष्टमी एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है जो भगवान विष्णु के दशावतारों में

से आठवें और चौबीस अवतारों में से बाईसवें अवतार श्रीकृष्ण के जन्म के आनन्दोत्सव के लिये मनाया जाता है। यह त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी की रात्रि को मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को जन्माष्टमी, कृष्ण जयंती और गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है। जन्माष्टमी का त्योहार दुनिया भर में बड़े उल्लास और आनंद के साथ मनाया जाता है। यह पवित्रता, स्वच्छता और विषमता का प्रतीक है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर खेला जाने वाला एक प्रसिद्ध खेल दही हांडी है जो जन्माष्टमी के अगले दिन मनाई जाती है। और यह खेल मुख्य रूप से महाराष्ट्र में खेला जाता है। यह त्योहार लोगों द्वारा उपवास रखकर, भक्ति गीत गाकर और रात्रि में जागरण करके मनाई जाती है। मध्यरात्रि के जन्म के उपरान्त, शिशु कृष्ण की मूर्तियों को धोया और सुंदर पोशाक पहनाया जाता है, फिर एक पालने में रखा जाता है। फिर उनकी पूजा-अर्चना करके जन्माष्टमी मनाई जाती है।

ग्राम-संपर्क अभियानः 7 दिवसीय पर्व नहीं 365 दिन का सम्पर्क चाहिए

-जयंत वर्मा
लेखक एवं विचारक

सत्ता और समाज पर नजरिया

(पिछले अंक से आगे)

मध्यप्रदेश में ग्राम-संपर्क अभियान का यह दूसरा प्रयोग था। आज भी अगर ग्रामवासी से बात करो, उसकी आर्थिक लाचारी की दास्तान सुनों, उसकी भूखमरी की हालात पर गौर करो और पूछो कि ग्राम संपर्क अभियान से उसे क्या लाभ मिला है, उत्तर नकारात्मक आवेगा। सत्रहवीं शताब्दी में फ्रांस में लुइस 16वें का शासन था। लोगों की दशा लगभग वैसी ही थी जैसी आम भारतवासी की आज है। जनता अपनी समस्या को लेकर आंदोलित होने लगी तो फ्रांस की रानी मेरी अन्टायनिटी ने पूछा कि लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उसे बताया गया कि लोगों की बुनियादी जरूरतें उन्हें नहीं मिल रही। इस पर रानी ने वास्तविक दशा से रूबरू होने की इच्छा जताई तो बड़े-बड़े कलाकर बुलाए गए और गरीबी क्या होती है, इसकी तस्वीर कैनवास पर उतारकर रानी को दिखाया गया। लोगों की समस्या जहां की तहां रही और कालांतर में ''फ्रांस की राज्यक्रांति'' हुई जिसका उल्लेख इतिहास की पुस्तकों में विस्तार से मिलता है। मध्यप्रदेश में भी आज यह स्थिति है कि सरकार की तमाम योजनाएं हैं। उन्हें लागू करने वाला अंध, मूक और बधिर प्रशासन है। सुनिश्चित रोजगार योजना में हर गरीब परिवार के सदस्य को वर्ष में 100 दिन काम देने की बात कही जाती है किन्तु जब ग्रामवासी इस योजना के तहत काम मांगता है तो उसे बताया जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, योजना लागू करने के लिए।

सरकार का हाल यह है कि प्रायः प्रत्येक विभाग को जो धनराशि या बजट आवंटित हो रहा है, उसमें से अधिकांश धनराशि उस विभाग के भारी-भरकम, अनुपयोगी और निकम्मे कर्मचारियों-अधिकारियों के वेतन-भत्तों में खर्च हो जाता है, जो विभाग जिस कार्य के लिये स्थापित है, उस कार्य को करने के लिये पैसा नहीं है। जिस प्रकार जलेबी सारा शीरा पी जाती है, उसी प्रकार सरकारी खजाने का पैसा आज सरकारी कर्मचारियों को पालने के लिये व्यय हो रहा है। क्या इस खर्च को रोकने के उपाय नहीं हो सकते? सरकारी वेतनभोगी लोगों की संख्या बढ़ाने के पीछे बुनियादी कारण यह है कि हमारे हुक्मरान जो हुजूरों से घिरे रहना चाहते हैं। प्रदेश की वंचित जनता को यदि वास्तव में लाभ पहुंचाना है तो उसके लिए हमें अपनी नीतियों पर गौर करना होगा। कड़ाई के साथ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो सुविधाभोगी वर्ग को अप्रिय लगें। सरकार के खजाने से एक पैसा भी यदि किसी को मिल रहा है तो उसका औचित्य देखना होगा। अनुपयोगी खर्चों को रोकने अनेक विभागों को बंद करना होगा- अयोग्य कर्मचारियों को सेवामुक्त करना होगा। भ्रष्ट तंत्र से निजात पाने के लिए सेवा संबंधी कानूनों में व्यापक फेरबदल करने होंगे। नौकरियों में रिटायरमेंट की आयु तक के लिए भर्ती करने की परंपरा पर पुनर्विचार करना होगा। एक स्वयंसेवी संस्था जो कार्य 10 रू. खर्च में पूरा कर लेती है, उस कार्य को करने में यदि सरकारी अमले को 100 रू. भी पूरे नहीं पड़ते तो फिर ऐसे सफेद हाथियों को पालते रहने की मजबूरी से मुक्त होने के कानून बनाए जाने चाहिए। एक ओर दो समय भोजन को मोहताज लाखों लोग और दूसरी ओर ऐसी जनता के कल्याण के लिए नियुक्त उत्तरदायित्व से मुक्त निकम्मा, भ्रष्ट और बेहद खर्चीला तंत्र। क्या इस पर गौर करना आज जरूरी नहीं हो गया है? क्रमशः

बांग्लादेश में हुंकार भरते हिंदू

-प्रमोद भार्गव

बांग्लादेश में संक्रमण के इस दौर में पिटते हुए नहीं, बल्कि हुंकार भरते हिंदु दिखाई दे रहे हैं। हिंदुओं का यह बदला रुख न केवल उनके लिए, उनके राष्ट्र का नागरिक बने रहने का अभिमान हैं, बल्कि शरणार्थी या घुसपैठिए की लाचारी से मुक्त बने रहने का स्वाभिमान भी है। उनकी इस भावना को समान देते हुए मुहम्मद यूनुस को कहना पड़ा है कि हिंदू देश के नागरिक हैं, अतएव उनके प्रति हर प्रकार की हिंसा तत्काल बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा भी कि हम ऐसी सरकार का गठन करेंगे, जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए यह भी कहा कि अगर आपको मुझ पर भरोसा है यह तय करना होगा कि देशभर में कहीं भी किसी पर कोई हमला नहीं किया जाए। यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो यहां मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। यह कथन इस बात का संकेत है कि यूनुस अब देष में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव एवं अन्याय नहीं देखेंगे। दरअसल यूनुस बुद्धिजीवी होते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इसलिए उन्हें तत्काल शेख हसीना या खालिदा जिया की तरह वोट-बैंक के लिए बहुसंख्यक हित साधने की जरूरत नहीं रह गई है।

बांग्लादेश में एकाएक तख्तापलट के बाद हालात बद से बदतर होते दिखाई दिए हैं। नतीजतन पुलिस बलों ने हड़ताल करके 650 थानों में तलाबंदी कर दी थी। इस कारण अराजकतावादी तत्वों को खुली छूट मिल गई और वे बांग्लादेश में रहने वाली लगभग 1 करोड़ 30 लाख की हिंदू आबादी वाली क्षेत्रों में आक्रमक होते दिखाई दिए। अतएव हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए स्वयं आगे आना पड़ा। एक हिंदू महिला के हाथ में हँसिया भी दिखा। यह हँसिया इस बात का प्रतीक रहा कि यदि किसी महिला से दुराचार की कोशिश अतातांइयों ने कि तो हिंदू स्त्री देवी दुर्गा की प्रतीक बनकर प्रतिहिंसक के अवतार में आ जाएगी। अपनी संगठन क्षमता दिखाने की दृष्टि से बांग्लादेश में हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में हिंदू व अन्य अल्पसंख्यक समुदाय राजधानी ढाका के शाहबाग में एकत्रित हुए और आगजनी, लूटपाट व हमलों के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में केवल हिंदु ही नहीं थे, बल्कि ईसाई और बौद्ध भी थे। इन लोगों ने हुंकार भरी कि 'हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। हम अपना देश (जन्मभूमि) छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और अपने पर हो रहे जुल्मों व बर्बर हिंसा का साहस के साथ प्रतिकार करेंगे।' बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद 64 जिलों में से 52 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ 205 हिंसक घटनाएं घट चुकी हैं। कई हिंदुओं के गांव जला दिए गए। नतीजतन लोगों को पलायन करना पड़ा। इस घटना को लेकर बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद ने अंतरिम सरकार के नेता मुहम्मद यूनुस को खुला पत्र लिखकर कहा है कि 'अल्पसंख्यकों में गहरी चिंता और अनिश्चितता है। सरकार को तत्काल ऐसे हालातों को संज्ञान में ले।' संयुक्त राष्ट्र की महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि 'हम बांग्लादेष में जारी हिंसा के बीच हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले के खिलाफ हैं। हम यह तय करना चाहते है कि तुरंत बांग्लादेश में चल रही हिंसा को नियंत्रित किया जाए। हम किसी भी नस्ल आधारित हमले या हिंसा भड़काने के उपायों के विरुद्ध खड़े हैं। हालांकि बांग्लादेश में विद्रोही इतने उग्र है कि वहां की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन को प्रदर्शनकारियों के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा है। लोग अदालत में घुसते चले गए थे।

इस बीच देखने में आया है कि संयुक्त राश्ट्र और मुहम्मद यूनुस तो हिंदुओं की सुरक्षा की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन भारत में कांग्रेस और विपक्षी दलों के ओंठ सिले हुए हैं। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने वक्तव्य में बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की न तो कोई बात की और न ही उनका कहीं कोई उल्लेख किया। कांग्रेस की इस मनस्थिति पर कटाक्ष करते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 'कांग्रेस गाजा और फिलिस्तीन को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करती है, वहां के हालात पर समय-समय पर चिंता जताती है। मगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोलती है। आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी को गाजा की तो चिंता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है।' याद रहे कांग्रेस व विपक्ष की इस वोट-बैंक की राजनीति के चलते कश्मीर में आतंक और अलगावाद बढ़ा, नतीजतन वहां से पांच लाख से भी ज्यादा हिंदू, सिख और बोद्धों को विस्थापन का दंष झेलना पड़ा। क्या कांग्रेस बांग्लादेश में भी हिंदुओं की यही दुर्दशा देखने की इच्छुक है?

हिंदूओं पर हमले, मंदिरों और दुर्गा पंडालों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हृदय विदारक घटनाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश में आम बात रही है। इन सब के बीच बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समाज की आवाज को मुखर ढंग से उठाया नहीं जा सका है। इसका बड़ा कारण है कि पिछले चार दाष्कों के दौरान वहां से हिंदूओं की आबादी पांच फीसदी घटकर 13.5 से मात्र 8.5 फीसदी रह गई है। बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन भारत में होता रहा है। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदूओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है, राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला जाना। परंपरागत रूप से हिंदू वोटर बांग्लादेश में सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थक रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद को धर्मनिरपेक्ष बताकर हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने का वादा तो करती रही हैं, लेकिन हमले की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश अपने कार्यकाल में कभी नहीं लगा पाईं। हिंदू बांग्लादेश में इसलिए कमजोर हुए, क्योंकि पलायन करके भारत का रुख करते गए। यह पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश के सभी अल्पसंख्यकों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और वहां की सरकार को देश का नागरिक होने के अधिकार को जताया। यदि हिंदू इसी दृढ़ता से पेश आते रहे तो उन्हें पलायन करके किसी अन्य देश का शरणार्थी बने रहने की जरूरत शायद नहीं रह जाएगी।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले एक निश्चित पद्धति के अनुसार होते रहे हैं। दंगों के पहले कुछ सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती है और इसे इस्लाम के खिलाफ करार दे दिया जाता है। फिर कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं पर हमले का फरमान जारी कर देते हैं। इसके बाद हमलों का दौर शुरू हो जाता है। उधर सरकार बस बयानबाजियां करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। ये बात अब अल्पसंख्यक खासकर हिंदू समुदाय भी समझ चुका है। लेकिन राजनीतिक रूप से हाशिए पर होने से कुछ नहीं कर पाते। हिंदू, बौद्ध व सिख अल्पसंख्यकों के निरंतर पाकिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर में संख्यात्मक रूप से कम होते जाने से स्थिति बिगड़ती जा गई है। अफगानिस्तान में भी यही हाल है। कुछ सालों के भीतर अफगानिस्तान से हिंदू और सिख लगभग पूरी तरह पलायन कर गए।

खिलाड़ियों की नौकरी का रास्ता साफः मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में बनी कमेटी

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति देना है। इस कमेटी में वनमंत्री केदार कश्यप, खेल मंत्री टंक राम वर्मा, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी, और खेल युवा कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल हैं। कमेटी की पहली बैठक मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सीएम हाउस में होगी। इस बैठक के बाद खिलाड़ियों की नियुक्ति का निर्णय लिया जाएगा। पिछली सरकार में खिलाड़ियों ने नौकरी की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन किया था।

9 साल से लंबित है खिलाड़ियों की नौकरी की मांग

2015 से राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। पिछले 9 साल से ये खिलाड़ी नौकरी की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, खेल मंत्री, और खेल विभाग के दरवाजे खटखटाने के बावजूद इन खिलाड़ियों की मांगें अनसुनी रह गई थीं।

जल्द जारी होगी खिलाड़ियों की सूची- प्राप्त जानकारी अनुसार, कमेटी की बैठक के बाद करीब 199 खिलाड़ियों की सूची जारी की जा सकती है। राज्य शासन के अधीनस्थ विभाग में इन खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी। खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने भी कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा जल्द होगी।

जनकल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। वाणिज्य एवं उद्योग और श्रम मंत्री एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने जिला कलेक्टोरेट खैरागढ़ के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री देवांगन ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो और उसका बेहतर लाभ आम नागरिकों तक प्राथमिकता के साथ पंहुचे। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करते हुए जनहित के कार्य करने प्रेरित किया। समीक्षा बैठक में राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे, खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा, पुलिस अधिक्षक त्रिलोक बंसल, जिला पंचायत राजनादगांव की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरुचि सिंह, अपर कलेक्टर सहित अन्य विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मंत्री देवांगन ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला अस्पताल के निर्माण के लिए जल्द से जल्द जगह चिन्हित करने को कहा। इसके अलावा जिले में ब्लड बैंक प्रारंभ करने की दिशा में तेजी से जुटने के निर्देश दिए। साथ ही मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिए तत्परता से जुट कर कार्य करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसी तरह जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को मंत्री देवांगन ने निर्देश देते हुए कहा की योजना को सिर्फ पूर्ण करने के बजाए घर-घर तक पानी भी मिले इसकी भी निगरानी करें। बैठक में मंत्री देवांगन ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सोच है की हर योजना का लाभ अधिक से अधिक आमजनों तक पहुंचे, इस दिशा में सभी विभाग समन्वय बनाकर काम करें। उन्होंने कहा कि यह नया जिला है, संसाधन की कमी अभी है, लेकिन आने वाले समय में विष्णु देव सरकार में क्षेत्र को किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा मंत्री श्री देवांगन को जिले की समस्याओं से अवगत कराया गया।

CBI ने अपने ही DSP को साढ़े 4 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा, विभाग में हड़कंप

-अर्चना शर्मा

जगत प्रवाह. जबलपुर। नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) सिंगरौली में सामान की अपूर्ति और अन्य भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रहे जबलपुर सीबीआई कैडर के डीएसपी को दिल्ली से पहुंची सीबीआई टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। शनिवार रात को डीएसपी को पकड़े जाने के बाद सीबीआई मुख्यालय के निर्देश पर रविवार को जांच एजेंसी की टीम एनसीएल के दो अधिकारियों और एक सप्लायर के आवास पर छापेमारी की। 16 घंटे चली इस छापेमारी में चार करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई है।एनसीएल में पूर्व सीएमडी भोला सिंह के कार्यकाल के दौरान मशीनों के कुलपुर्जों की सप्लाई हुई थी। इसमें अनियमितता की शिकायत हुई थी। मामले की जांच सीबीआई जबलपुर काडर के डीएसपी जाय जोसेफ दामले को सौंपी गई थी। शनिवार की रात डीएसपी को सीबीआई मुख्यालय की टीम ने जबलपुर के विजय नगर स्थित एसबीआई चौक से साढ़े चार लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इसके बाद सीबीआई मुख्यालय की टीम ने एनसीएल के मुख्य सुरक्षा अधिकारी बसंत कुमार सिंह, सीएमडी के प्रबंध सचिव सूबेदार ओझा व ठेकेदार रवि सिंह के आवास और कार्यालय पर छापेमारी की। सीबीआइ को प्रबंध सचिव के आवास से साढ़े तीन करोड़ रुपये नकद मिले। मुख्य सुरक्षा अधिकारी और ठेकेदार के यहां भी 50 लाख रुपये मिले। कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। टीम मुख्य सुरक्षा अधिकारी बसंत कुमार सिंह और सीएमडी के प्रबंध सचिव को हिरासत में लेकर जबलपुर चली गई। (शेष पेज 2 पर)

प्रतिबंध से विचार नहीं मिटते

-रघु ठाकुर

पिछले अठावन वर्षों से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सरकारी कर्मचारियों को एक प्रकार का प्रतिबंधित संगठन जैसा था। यद्यपि संघ शाखाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं था परंतु सरकारी कर्मचारियों का आरएसएस शाखा में भाग लेना प्रतिबंधित था। वैसे यह प्रतिबंध भी बहुत प्रभावी नहीं था, क्योंकि संघ की राजनैतिक संतान भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्वाचित होकर राज्य और केंद्र की सरकारों में सहभागी बनने लगे थे। और प्रतिबंध केवल शाब्दिक जैसा रह गया था। जब देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री, राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्री शाखाओं में जाते हैं, उनके चित्र अखबारों में छपते हैं तो प्रतिबंध कहाँ रहेगा? परंतु वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने अचानक बगैर किसी मांग के तकनीकी रूप से संघ की शाखा में भाग लेने पर प्रतिबंध को हटा दिया। इससे कई प्रकार की चर्चाएँ शुरू हुई हैं और भारतीय राजनीति के एक धड़े के नेताओं में विशेषतरू इंडिया गठबंधन के नेताओं और मीडिया के एक हिस्से के द्वारा इस बात की आलोचना हो रही है और संघ पर, उसकी राजनैतिक और सांस्कृतिक भूमिका पर, उसके सांस्कृतिक ढांचे पर राष्ट्रव्यापी चर्चा आरंभ हुई है कि केंद्र सरकार के इस आदेश से संघ के लोगों और विशेषकर अधिकारियों, कर्मचारियों को शाखा में जाने की स्वतंत्रता हो जाएगी इसका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ेगा, तथा इससे संघ का प्रभाव और अधिक व्यापक होगा।

देश के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी ऐसी ही आशंका व्यक्त की और लेख लिखे हैं। एक पत्रकार महोदय ने तो सुप्रीम कोर्ट से अपील की है और यह अपेक्षा की है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतरू संज्ञान लेकर भारत सरकार के इस आदेश को निरस्त करें। मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना उचित होगा या सुप्रीम कोर्ट लेगा, यह आश्चर्य की बात है कि वे स्वतः याचिका दायर क्यों नही कर रहे हैं? और अगर उन्हें अपने लेखन पर विश्वास है तो स्वतः आगे क्यों नहीं आ रहे? जहां तक संघ का राजनैतिक या सांस्कृतिक संगठन होने का प्रश्न है तो पिछले अठावन वर्षों में यह सभी लोग जान चुके हैं कि संघ का मुखौटा सांस्कृतिक है परंतु वास्तव में वह राजनैतिक ही है, जो दल का निर्माण करता है, दलों को बनाता-मिटाता है, चुनाव में हिस्सेदारी करता है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिये नाम तय करता है। भाजपा सरकारों को नियंत्रित करता है और अपने स्वयं सेवकों के माध्यम से सरकारों को चलाता है। संघ की यह भूमिका कोई आज की नहीं है वरन पुरानी है। संघ के दूसरे सरसंघ संचालक और विचार पुरुष स्वर्गीय गोलवलकर जी ने जिन्हें संघ के लोग शास्वत गुरु मानते हैं, ने अपनी पुस्तक विचार नवनीत्य में लिखा था कि संघ राजनैतिक दल को बनायेगा या उसे चलायेगा और अगर वह दल उपयोगी नहीं रहा तो उसे खत्म करेगा। उनके शब्दों में बनाया जाने वाला राजनैतिक दल कमल की नली के समान होगा जो जब तक बजेगी तब तक बजायेंगे और जब बजना बंद हो जायेगी तो फिर उसे खा जायेंगे।

यह आश्चर्य की बात है कि संघ की यह भूमिका पिछले अट्ठावन वर्षों से घोषित अघोषित रूप से हो रही है। यह भी

आश्चर्यजनक है कि जो कांग्रेस के मित्र अब कर्मचारियों को संघ शाखा में जाने की अनुमति पर चिंतित है उन्हीं की आजाद भारत की पहली सरकार ने संघ पर प्रतिबंध भी लगाया था और फिर उसे हटाया भी था। इतना ही नहीं संघ को देश में रचनात्मक कार्यों जैसे गणतंत्र दिवस आदि में सहयोग के लिये आमंत्रित किया था। क्या ये कांग्रेस के मित्र इसे अपने सत्ताधीश पुरखों की गलती स्वीकार करेंगे? या फिर केवल बढ़ी हुई ताकत से भयभीत होकर प्रतिबंध की बात उठा रहे हैं।

भले ही औपचारिक रूप से संघ की शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के जाने पर प्रतिबंध लगा हो परंतु उस प्रतिबंध का क्या प्रभाव होगा विशेषकर जब देश का प्रधानमंत्री, गृहमंत्री ही शाखाओं से प्रशिक्षित होकर सत्ता में आया हो, पंद्रह वर्षों तक संघ के लोग केंद्र में सत्ताधीश रह चुके हो और शासन प्रशासन के नियंत्रक तथा कर्ता-धर्ता रहे हों।

मैं इस प्रतिबंध का समर्थक नहीं हूँ और मानता हूँ कि किसी विचारधारा से संघर्ष या मुकाबला सत्ता के प्रतिबंधों से नहीं हो सकता, वह तो विचारधारा के माध्यम से ही होना चाहिये। आजादी के पहले कांग्रेस पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगाया था तो क्या उससे कांग्रेस समाप्त हुई? 1962 में चीनी हमले के के बाद तत्कालीन सरकार ने कम्युनिष्टों पर प्रतिबंध लगाया था, क्या कम्युनिष्ट पार्टियां समाप्त हुई? आपातकाल में कांग्रेस सरकार ने जनसंघ और अन्य राजनैतिक दलों तथा संघ पर अघोषित प्रतिबंध लगाया था तो क्या वे समाप्त हो गये? प्रतिबंध अमूमन प्रतिबंधित विचार को और अधिक फैलाता तथा बढ़ाता है। जिस प्रकार पेड़ की कांटछांट से पेड़ घटता नहीं बल्कि बढ़ता है।

संघ की विचारधारा निसंदेह सांप्रदायिक है, जो संस्था एक देश के एक ही धर्म को मानती हो, जो देश को एक हिंदू धर्म का राष्ट्र बनाना चाहती हो, उसमें धार्मिक कट्टरता होना स्वाभाविक है। एक धर्म के राष्ट्र की परिकल्पना भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता समभाव और बंधुता के खिलाफ है। एक धर्म या देश मानने वाली जमातें कहे-अनकहे, घोषित या अघोषित, चाहे या अनचाहे अपने प्रति उदार और अन्यों के प्रति कट्टर होती हैं। यह स्थिति हम लोग दुनिया के उन देशों में भी देख सकते हैं जहां एक धर्म के देश वह पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, ईरान, ईराक या कोई भी एक धर्म को मानने वाले देश हैं, वहाँ दूसरे धर्मों को मानने वालों की स्थिति स्वाभाविक रूप से दोयम दर्जे की हो जाती है। और वह अंतंकलह अंतरहिंसा में बदलती है जिसको हम लोग पाकिस्तान या अन्य देशों में देख रहे हैं। संघ की संकीर्णता प्रतिबंध से हटती नहीं है वरन बढ़ती है। एक धर्म का देश होना फिर उसमें बहुमत वाले एक पंथ का देश होगा, फिर पुरानी परंपराओं को पुनः जिंदा कर चलाने वाला देश होगा और अंतत वह विघटन की ओर ले जायेगा। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेकों धर्म हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, सैकड़ों जातियाँ व उपजातियाँ हैं इन्हें एकजुट रखना ही देश को ताकतवर बनाना होगा और इसके लिये सभी धर्मों, भाषाओं, क्षेत्रों, खंडों, उपखंडों की स्थानीयता के साथ-साथ एक सुगठित राष्ट्र बनाना होगा। परस्पर मत भिन्नताओं के बीच संवाद करना होगा तथा भिन्नताओं को बहुमत की शक्ति के बजाय आम सहमति से काम करना होगा।

संघ के लोग अभी तक भले ही खुलकर शाखाओं में न जाते हों, परंतु संघ के अधिकारियों और कर्मचारियों की मूल वैचारिक निष्ठा तो संघ में ही रहती हैं तथा एक छिपी हुई भावनात्मक और संगठनात्मक एकता भी उनमें रहती है। यहाँ तक कि अधिकारी वर्ग संघ के अलिखित निर्णय या आदेशों को प्रशासन में क्रियान्वित करता है। संघ और उसके राजनैतिक दल की संरचना ही ऐसे बनाई गई है जिस प्रकार कम्युनिस्ट शासन में पार्टी ही सत्ता बन जाती है उसी प्रकार भाजपा शासन में संघ ही सत्ता का केंद्र बन जाता है। संघ के प्रशिक्षित लोग पार्टी (भाजपा) में संगठनमंत्री के रूप में भेजे जाते हैं और वे ही पार्टी और सरकार को नियंत्रित करते हैं इसलिये भाजपा की सत्ता वास्तविक रूप से संघ की सत्ता होगी यह बात किसी से भी छिपी नहीं है।

संघ अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने आप को रूपांतरित और परिभाषित करता है। वह सांस्कृतिक भी बन सकता है, वह गैर राजनैतिक भी बन सकता है और आवश्यकता पड़ने पर संपूर्ण राजनैतिक भी हो सकता है। मुझे याद है कि 1978-79 के बीच संघ ने नागपुर में आयकर विभाग को लिखकर दिया था कि वह राजनैतिक है। इसलिये संघ की शाखा में कर्मचारियों के प्रवेश की रोक का कोई असर न हुआ था न होगा। पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट के जज अभी 2024 के चुनाव में सेवानिवृत्ति के बाद लोकसभा का चुनाव भाजपा से लड़े। एक और जज साहब ने हाल ही में सेवानिवृत्ति के बाद बयान दिया है कि वे संघ के हैं। और ऐसे कितने ही अधिकारियों, न्यायाधीशों को मैं जानता हूँ (इनकी नियुक्ति अधिकांशतः कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी) क्योंकि उनकी पहचान संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों के संघ की शाखाओं में जाने के प्रतिबंध हटाने के बाद कुछ अच्छे परिणाम भी निकल सकते हैं...

1. अब प्रशासन में संघ के स्वयंसेवकों की पहचान खुलकर सामने आयेगी और उनका संगठनात्मक पक्ष भी छिप नहीं सकेगा।
2. संघ के अधिकारी अब प्रशासनिक निर्णयों की जवाबदारी से बच नहीं सकेंगे।
3. बुराई अगर छिपी रहे तो ज्यादा भ्रामक व घातक होती है पर अगर वह खुलकर सामने आ जाये तो कम से कम पहचान तो आसान हो जाती है।
4. छिपी शक्ति से मुकाबला कठिन होता है, बजाय सामने के शक्ति से मुकाबले में। अगर देश के राजनैतिक दल संघ के विचार का मुकाबला वैचारिक आधार पर करना चाहेंगे तो अब ज्यादा आसान होगा।
5. प्रतिबंध से विचार तेजी से फैलते हैं और उनका फैलाव छिपा रहता है, जो नजर नहीं आता है।
6. सरकारी कर्मचारी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य हो सकता है, पर शाखा में नहीं जायेगा, क्या यह अंर्तविरोधी और केवल दिखावटी प्रतिबंध जैसा नहीं है?

2200 करोड़ के शराब घोटाले मामले में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की EOW को मिली रिमांड

-संवाददाता

जगत प्रवाह.रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुए 2200 करोड़ के शराब घोटाला मामले में ACB के स्पेशल कोर्ट ने रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को 7 दिन की सशर्त रिमांड पर EOW को सौंप दिया है। EOW ने ACB कोर्ट में रिमांड के लिए आवेदन किया था। हाईकोर्ट के आदेश के कारण EOW ने इस मामले में टुटेजा की अब तक गिरफ्तारी नहीं की थी। बता दें कि 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में ईडी और EOW के खिलाफ दायर 13 याचिकाओं को खारिज किया है। इसके साथ ही अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से मिला संरक्षण भी खारिज हो गया। इसके बाद EOW ने कोर्ट में अनिल की प्रोडक्शन वारंट के लिए याचिका लगाई थी। कोर्ट ने आवेदन स्वीकार कर लिया। EOW की ओर से रिमांड मांगे जाने के पहले ही अनिल टुटेजा के वकील ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर गिरफ्तारी करने पर कोर्ट के समक्ष आपत्ति किया जिसको खारिज करते हुए एसीबी स्पेशल कोर्ट ने अनिल टुटेजा को सशर्त EOW को रिमांड पर सौंपा है। EOW की ओर से जो शर्तें रखी गई है, उसमें आरोपी के मानवाधिकारों की रक्षा करने, दुर्व्यवहार या मारपीट या शारीरिक प्रताड़ना न देने और टुटेजा के अधिवक्ताओं से गरिमापूर्ण व्यवहार रखने की शर्तें शामिल हैं। इसके साथ ही रिमांड अवधि में समुचित दवाएं और इलाज मुहैया कराने, परिजनों से मिलने की अनुमति देने की याचना अनिल टुटेजा के वकील की ओर से की गई थी। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया है।

कलम के सिपाही...

पत्रकारिता के साथ समाजसेवा में भी योगदान देते थे अयोध्या प्रसाद गुप्ता

13 जनवरी 1927 में मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में जन्में अयोध्या प्रसाद गुप्ता जी का पत्रकारिता जीवन खट्टे-मीठे अनुभवों से भरा रहा। सागर विश्वविद्यालय, सागर से स्नातक की पढ़ाई की। लेखन का शौक बचपन से रहा। स्कूली शिक्षा लेते समय सेवा से जुड़े कार्य उनके व्यक्तित्व को बहुत भाते थे। आप सन 1953 से समाजसेवा के कार्यों से जुड़कर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। यह सिलसिला जीवनपर्यंत चला। आपने जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में नवयुवक मण्डल का गठन किया व व्हालीबॉल, कबड्डी इत्यादि खेल प्रतियोगिता का कई सालों तक लगातार आयोजन किया। गणेशोत्सव, दुर्गा उत्सव जैसी धार्मिक गतिविधियों की जिम्मेवारी भी आगे रहकर निभायी। पत्रकार का जीवन साधना और संघर्षों से भरा रहता है। समाचार की सच्चाई और तथ्यों को जानने की अभिलाषा सदैव बढ़ती जाती है। वे कहते और मानते भी रहे कि खुद को इस क्षेत्र में विद्यार्थी समझते रहना ही हितकारी है जो आगे का मार्ग दिखाता जाता है। ऐसा उन्होंने जीवन पर्यन्त किया। खबर प्रकाशन से पहले तथ्यों की सत्यता की जाँच ठोंक बजाकर करते और प्रकाशन के बाद उसका तुलनात्मक विश्लेषण करते। खबर लेखन के समय व्यक्तिगत राग-द्वेष आड़े न आए, ऐसा हमेशा ख्याल रखा। किसी का अकारण अहित न हो, यह उनकी कोशिश हमेशा रही।

पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्ष 1949 में आए। वर्ष 1951 से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाते हुए प्रथम आम चुनाव 1952 में समाचार लेखन किया। जबलपुर से प्रकाशित दैनिक युगधर्म, दैनिक नवभारत टाइम्स मुम्बई, दैनिक आज व अंग्रेजी दैनिक दी लीडर, इलाहाबाद समाचार पत्रों के साथ जबलपुर से प्रकाशित साप्ताहिक प्रहरी का प्रतिनिधित्व करते हुए समाचार लेखन किया। सन 1959-60 से पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकार के नाते हिन्दुस्तान समाचार, समाचार अभिकरण, भोपाल, दिल्ली, आगरा में महत्वपूर्ण पदों पर रहकर लगातार कार्य किया। सन् 1967 से 1971 के मध्य तक दिल्ली में केन्द्र सरकार द्वारा अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार के नाते कार्य करने के बाद कुछ महीने हिन्दी समाचार अभिकरण न्यूज एजेंसी में रहे। दैनिक नवभारत, भोपाल में उप सम्पादक के नाते वर्ष 1980 तक कार्यरत रहे। इसके बाद दिल्ली में रूपक अभिकरण, इण्डिया एण्ड फ़ीचर एलायन्स, इन्फा का म.प्र. की राजधानी भोपाल में रहकर प्रभारी पद का दायित्व निभाया। साथ ही राजनैतिक डायरी, देश विकास की गतिविधियाँ, सामयिक आलेख, नियमित लेखन का क्रम भी जारी रखा। दिल्ली में रहते हुए हिन्दी दैनिक स्वदेश इन्दौर में विविध विषयों पर आलेख लिखे जिनका प्रकाशन नियमित होता रहा। भोपाल में भी दैनिक नवभारत के बाद दैनिक देशबन्धु भोपाल के सम्पादकीय विभाग में रहे। आपको सम्पन्न परिवार में जन्म लेने और बढ़ने का अवसर मिला पर जीवन में कमियाँ तो आकार लेती ही रही। अखबारी दुनिया में कदम बढ़ाते समय आर्थिक परेशानियों से जूझना ही होगा, यह जानते हुए भी कदम-दर-कदम आगे बढ़ते रहे। समाज के विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों में कार्यरत रहे और अधिकारियों राजनेताओं के सम्पर्क में आने के कारण कार्यक्षेत्र, सम्पर्क क्षेत्र बढ़ता रहा। इसका व्यक्तिगत स्तर पर लाभ उठाने की कोशिश उन्होंने कभी नहीं की। वह समाचार लेखन के समय सदैव ध्यान रखते कि तथ्य सटीक और सच्चे हों और समाज-देश पर उसका विपरीत प्रभाव न पड़े। जीवन पर्यन्त विद्यार्थी बनकर सीखने के लिए तैयार रहना उनके व्यक्तित्व का अनूठा पहलू था। उन्हें हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग (उ.प्र.) से 'साहित्य रत्न' की उपाधि दी गई। 20 फरवरी 2017 को उन्होंने इस जीवन से विदा ली और पत्रकारिता जगत में अपना स्थान सूना कर गये।

ओवर लोडिंग एवं भारी वाहन शहर के अंदर प्रवेश ना होने दें, स्कूल वाहनों में अधिक मात्रा में बच्चे ना बैठें

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। कलेक्ट्रेट कार्यालय के रेवास सभा कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर डॉ. बबीता राठौर ने विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा कर संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में डीएसपी ट्रैफिक संतोष मिश्रा, आरटीओ श्रीमती निशा चौहान, एमपीआर डीसी, एनएचआई, पीडब्ल्यूडी, विधुत विभाग, नगर पालिका नर्मदापुरम, शिक्षा, एमपीआरआरडीए के विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में डिप्टी कलेक्टर डॉ. बबीता राठौर ने निर्देश दिए कि व्यवस्थित यातायात के संबंध में प्रमुख चौराहों पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शीघ्र की जाए। सड़क सुरक्षा के संबंध में प्रमुख स्थानों पर आवश्यक साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर और क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत कराई जाए। उन्होंने एमपीईबी और नगर पालिका नर्मदापुरम को निर्देश दिए कि जिस सडकों एवं हाईवे के किनारे विधुत पोल एवं लाईट नहीं है वहां लाईट लगवाए। उन्होंने नगर पालिका से कहा कि गोवंश को रोड से हटाने के लिए हाका गैंग को एक्टिव मोड में रखें तथा सब्जी और खाने के ठेले शहर के मुख्य रोड के किनारे एवं बाजार में लगे रहते हैं उनको निर्धारित स्थान पर लगवाएं। उन्होंने नगर पालिका से कहा कि रोड किनारे के पास से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए।बैठक में डिप्टी कलेक्टर डॉ बबीता राठौर ने कहा कि प्रत्येक शासकीय कर्मचारी हेलमेट लगाकर गाडी चलाए। बैठक में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी निशा चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल वाहनों में बच्चों को सीमित मात्रा में बैठाया जाए। उन्होने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत शहर के विभिन्न स्कूल संचालकों को ध्यान देना चाहिए की स्कूल वाहन का परमिट और चालक के पास वैध लाईसेंस है कि नहीं तथा अधिक मात्रा में बच्चों को स्कूल वाहन में अधिक मात्रा में ना बैठाया जाए।

(पेज 6 का शेष)

आधी रात के बाद पहुंची सीबीआई टीम

भ्रष्टाचार की शिकायत पर जबलपुर से आई सीबीआई टीम एनसीएल के सीएमडी के पीए सूबेदार ओझा के आवास पर शनिवार आधी रात के बाद करीब एक बजे पहुंची। इसी दौरान टीम के कुछ सदस्य एनसीएल के मुख्य सुरक्षा अधिकारी बसंत कुमार सिंह के आवास पर पहुंचे और पूछताछ व कागजात की जांच के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया।

ठेकेदार के घर पर भी छापेमारी

ठेकेदार रवि सिंह के विंध्यनगर स्थित घर पर भी इसी समय छापेमारी की गई। सीबीआइ टीम की कार्रवाई 16 घंटे तक चली। इस संबंध में सीबीआइ टीम के अधिकारी कुछ भी जानकारी देने से बचते रहे। सूत्रों के मुताबिक विभिन्न प्रकार के सामान की आपूर्ति और अन्य मदों में भ्रष्टाचार की शिकायत पर सीबीआइ ने यह कार्रवाई की।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)